



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2006/चैत्र 10, 1928

No. 318]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2006/CHAITRA 10, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2006

का. आ. 475(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 603(अ) के माध्यम से सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17-9-1991 से अशान्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विचार से उक्त जिलों की स्थिति इतनी अशान्त और खतरनाक हो गयी थी कि वहाँ सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी हो गया था।

2. भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) 1982 की सं. 550 में अपने दिनांक 27 नवम्बर, 1997 के निर्णय के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशान्त क्षेत्रों' की घोषणा की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। तदनुसार, अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा की सितम्बर 2005 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 31 मार्च, 2006 तक बढ़ाया गया।

3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुनः समीक्षा की गयी है। अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों में विद्रोह से संबंधित परिदृश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैन्ड (एन एस सी एन) तथा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ असम (उल्फा) दोनों गुटों द्वारा सुरक्षा बलों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाइयों सहित जबरन धन वसूली तथा हिंसक कार्रवाइयों सतत रूप से की जा रही हैं। एन एस सी एन के गुटों के बीच पारस्परिक दुश्मनी के कारण भी इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गयी है। अतः अरुणाचल प्रदेश के इन दोनों जिलों में विद्रोही गुटों के विरुद्ध प्रभावी विद्रोह-रोधी अभियान चलाया जाना आवश्यक है।

4. अतः केन्द्रीय सरकार का विचार है कि तिरप एवं चांगलांग जिलों में हालात अशान्त हैं और वहाँ ऐसी स्थितियाँ मौजूद हैं जिनके कारण सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अतः यह निर्णय किया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना को 30 सितम्बर, 2006 तक, बशर्ते कि यह पहले वापस न ले ली जाए, प्रभावी रखा जाए।

[फा. सं. 13/27/99-एमजैड]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

(1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2006

S. O. 475(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. Supreme Court of India vide their judgment dated 27th November, 1997 in Writ Petition (Criminal) No. 550 of 1982 directed, *inter alia*, that declaration of 'disturbed areas' under the aforesaid Act should be reviewed periodically. Accordingly, the declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2005 and tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended up to 31st March, 2006.

3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. The insurgency related scenario in these districts of Arunachal Pradesh remains unchanged. The two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) and United Liberation Front of Assam (ULFA) continue to extort and indulge in acts of violence including those directed against the security forces. Intergroup rivalry between the factions of NSCN has also vitiated the law and order situation in these two districts. Therefore, effective counterinsurgency operation against the insurgent outfits in these two districts of Arunachal Pradesh is necessary.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exists for the use of the Armed Forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force up to 30th September, 2006 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.